



2026:AHC:30066

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2819/2026

माया देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : अमित्य सिंह, महेन्द्र प्रताप यादव, राम केश

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मुख्य रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत वाद संख्या 8378/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514360108378) को एक निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निस्तारण एक समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:

"(3). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर संपन्न की जाएगी।"

5. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वे उपरोक्त वाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"